REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 10 | JULY - 2021

सरगुजा जिले में वाणिज्य को बढ़ाने में वित्तीय समावेशन और इसकी भूमिका

डॉ. शैहून एक्का
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शासकीय नवीन महाविद्यालय, बतौली, जिला - सरगुजा (छ. ग.).

सारांश:

शोध पत्र भारत के सरगुजा जिले में वित्तीय समावेशन और वाणिज्य के बीच संबंध की जांच करता है। यह आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में वित्तीय समावेशन के महत्व पर प्रकाश डालता है, खासकर वंचित क्षेत्रों में। अध्ययन में पहुंच में आने वाली बाधाओं की पहचान की गई है , जैसे कि बुनियादी ढांचे की कमी, कम वित्तीय साक्षरता और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां। स्थानीय उद्यमियों , वित्तीय संस्थानों और नीति निर्माताओं के साथ सर्वेक्षण और साक्षात्कार सहित मिश्रित-विधि दृष्टिकोण से पता चलता है कि ऋण , बचत और बीमा तक बेहतर पहुंच छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाती है , आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है और रोजगार सृजन और आजीविका में वृद्धि करती है। यह पत्र वित्तीय समावेशन पहलों को बढ़ाने के लिए नीतिगत सिफारिशों के साथ समाप्त होता है, जिसमें सरकार, वित्तीय संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

मुख्य शब्द: वित्तीय समावेशन, वाणिज्य, सरगुजा जिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त तक पहुँच.

परिचय:

वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो समाज के सभी वर्गों , विशेष रूप से हाशिए पर पड़े या वंचित लोगों को सुलभ और सस्ती वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करती है। भारत में , जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है , वित्तीय समावेशन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बदलने , व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समग्र सामाजिक कल्याण को बढ़ाने की क्षमता है। यह शोध पत्र सरगुजा जिले पर केंद्रित है , जो अपनी समृद्ध कृषि विरासत और विविध आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है , और इस क्षेत्र में वाणिज्य को बढ़ाने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका की जाँच करता है।

भारत के छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित सरगुजा जिला अपने पहाड़ी इलाकों , हरे-भरे जंगलों और मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी के लिए जाना जाता है। जिले में विभिन्न जनसांख्यिकीय समूह शामिल हैं , जिनमें स्वदेशी समुदाय भी शामिल हैं , जिनमें से प्रत्येक इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक विविधता में योगदान देता है। सरगुजा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है , जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती, पशुपालन और संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है। जिले की आर्थिक गतिविधियों में वानिकी , हस्तशिल्प और लघु उद्योग भी शामिल हैं , जो आय सृजन के अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि , अपने संसाधनों के बावजूद , सरगुजा को सीमित बुनियादी ढांचे , बाजारों तक अपर्याप्त पहुंच और वित्तीय साक्षरता के निम्न स्तर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है , जो आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं।

सरगुजा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है , जहां औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आजीविका और व्यावसायिक संचालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। ऋण , बचत, बीमा और भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर, वित्तीय समावेशन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने , जोखिमों का प्रबंधन करने और भविष्य की योजना बनाने में सक्षम बनाता है। यह व्यवसायों को शुरू करने और विस्तार करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है , जिससे नौकरियां पैदा होती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा , वित्तीय समावेशन में वृद्धि आर्थिक झटकों के खिलाफ सामुदायिक लचीलापन बढ़ा सकती है और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।

इस शोध का उद्देश्य यह समझने में योगदान देना है कि सरगुजा जिले में आर्थिक सशक्तिकरण और वाणिज्य वृद्धि के लिए एक उपकरण के रूप में वित्तीय समावेशन का लाभ कैसे उठाया जा सकता है , अंततः सतत विकास को बढ़ावा देना और इसके निवासियों की आजीविका में सुधार करना।

शोध के उद्देश्य:

१) सरगुजा जिले में व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए बैंकिंग , ऋण, बीमा और बचत विकल्पों जैसी वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच का आकलन करना।
२) महिलाओं, किसानों और छोटे व्यवसाय मालिकों सहित विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों के लिए वित्तीय समावेशन में बाधा डालने वाली सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अवसंरचनात्मक चुनौतियों की जाँच करना।
३) यह जाँच करना कि वित्तीय सेवाओं तक पहुँच स्थानीय अर्थव्यवस्था के भीतर व्यवसाय संचालन , विकास और स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है, रोजगार सृजन, राजस्व वृद्धि और उद्यमशीलता गतिविधियों जैसे संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करना।
४) आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता के स्तर का पता लगाना और यह आकलन करना कि यह वित्तीय सेवाओं के उपयोग और समग्र आर्थिक भागीदारी को कैसे प्रभावित करता है।
५) सरगुजा जिले में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निकायों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लागू की गई पहलों और नीतियों और वाणिज्य को बढ़ाने में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।

साहित्य समीक्षा:

वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है , विशेष रूप से दक्षिण एशिया में , जहाँ वित्तीय सेवाओं तक बढ़ी हुई पहुँच आर्थिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है , विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के माध्यम से। विश्व बैंक की रिपोर्ट विभिन्न आयामों में वित्तीय समावेशन को मापने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है , जिसमें वंचित आबादी के बीच आर्थिक भागीदारी के लिए वित्तीय सेवाओं के महत्व पर जोर दिया गया है। सरमा वित्तीय सेवाओं की पहुंच , उपयोग और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन को मापने के लिए एक सूचकांक प्रस्तुत करते हैं।

कुमार और गुप्ता (२०१५) भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में वित्तीय समावेशन की भूमिका का विश्लेषण करते हैं , जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता का समर्थन करने और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवाएं आवश्यक हैं। घोष और साहू (२०१४) भारत में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं की जांच करते हैं , जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में बाधा डालने वाली अवसंरचनात्मक कमी , कम वित्तीय साक्षरता और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं जैसी चुनौतियों की पहचान की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (२०११) भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति पर रिपोर्ट करता है , जिसमें बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित किया गया है , खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने में भी आवश्यक है, जिसमें वित्तीय साक्षरता के स्तर और वित्तीय सेवाओं के उपयोग के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध है , जो बदले में स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है।

ज़िंस और वेइल (२०१६) अफ्रीका में वित्तीय समावेशन के निर्धारकों पर चर्चा करते हैं , चर्चा करते हैं कि कैसे आर्थिक विकास , बुनियादी ढाँचा और विनियामक ढाँचे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच और समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। भट्टाचार्य और

रंजन (२०१६) भारत में वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास के बीच परस्पर क्रिया का पता लगाते हैं , तर्क देते हैं कि ग्रामीण व्यवसायों को बनाए रखने और समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच महत्वपूर्ण है।

सिंह और कुमार (२०१५) विभिन्न भारतीय राज्यों में आर्थिक सशक्तिकरण पर वित्तीय समावेशन के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं , यह बताते हुए कि वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच आय के स्तर और व्यवसाय के विकास के साथ सहसंबद्ध है , विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। समीक्षा किए गए साहित्य में वाणिज्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से सरगुजा जिले जैसी ग्रामीण क्षेत्र में।

शोध पद्धति:

शोध अध्ययन का उद्देश्य सरगुजा जिले में वाणिज्य को बढ़ाने में वित्तीय समावेशन की भूमिका की जांच करना है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों को मिलाकर मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करता है। सर्वेक्षण , साक्षात्कार, साहित्य समीक्षा और सरकारी रिपोर्टों के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया है। नमूना आकार लगभग १०० स्थानीय व्यवसाय है , और सांख्यिकीय साधनका उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य वित्तीय समावेशन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों पर इसके प्रभाव की व्यापक समझ प्रदान करना, कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और नीति अनुशंसाओं की पहचान करना है।

सरगुजा जिले में वाणिज्य को बढ़ाने में वित्तीय समावेशन और इसकी भूमिका:

वित्तीय समावेशन सभी व्यक्तियों , विशेष रूप से हाशिए पर और वंचित आबादी के लोगों के लिए बैंकिंग , ऋण, बीमा और बचत जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। भारत के उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित सरगुजा जिले में , वित्तीय समावेशन वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विविध कृषि पद्धतियाँ इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं, जिसमें कृषि प्राथमिक क्षेत्र है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का महत्व कई मायनों में स्पष्ट है। यह स्थानीय समुदायों को सूचित निर्णय लेने , जोखिम प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता में सुधार करके सशक्त बनाता है। महिलाओं और छोटे किसानों सहित हाशिए पर पड़े समूहों के बीच आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए यह सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। वित्तीय समावेशन उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने की अनुमति देकर उद्यमशीलता के विकास को सुगम बनाता है , जिससे रोजगार सृजन होता है और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। बीमा उत्पादों तक पहुँच व्यक्तियों और व्यवसायों को अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने , निरंतर आर्थिक गतिविधि बनाए रखने की अनुमति देती है। वित्तीय सेवाएँ बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं , जिससे व्यक्तियों को शिक्षा , स्वास्थ्य और व्यावसायिक उपक्रमों में भविष्य के निवेश के लिए पूंजी बनाने की अनुमति मिलती है , जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। हालाँकि , सरगुजा जिले में बाधाएँ मौजूद हैं , जैसे कि बुनियादी ढाँचे की कमी , कम वित्तीय साक्षरता , गरीबी, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं और अपर्याप्त सरकारी और संस्थागत समर्थन के कारण बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुँच।

शोध से संकेत मिलता है कि वित्तीय समावेशन सरगुजा जिले में स्थानीय वाणिज्य को व्यापार के अवसरों में वृद्धि , रोजगार सृजन, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) की वृद्धि और बढ़ी हुई बाजार भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। ऋण तक पहुँच छोटे व्यवसायों को इन्वेंट्री में निवेश करने , संचालन का विस्तार करने और नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाती है , जिससे उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ती है। वित्तीय रूप से सशक्त उद्यमी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं , बेरोजगारी को कम कर सकते हैं और जिले में समग्र आर्थिक स्थितियों में योगदान दे सकते हैं।

वित्तीय समावेशन सरगुजा जिले में वाणिज्य और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाकर, स्थानीय समुदाय उद्यमिता और आर्थिक विकास के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वित्तीय समावेशन की बाधाओं को दूर करना, जैसे कि बुनियादी ढाँचे में सुधार , वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और हाशिए के समूहों को लक्षित सहायता प्रदान करना , अधिक समावेशी आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। नीति निर्माताओं , वित्तीय संस्थानों और सामुदायिक संगठनों को प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने के लिए सहयोग करना चाहिए जो वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हैं और सरगुजा जिले के निवासियों को सशक्त बनाते हैं , अंततः सतत आर्थिक विकास और बेहतर आजीविका में योगदान करते हैं।

परिणाम:

सरगुजा जिले में १०० स्थानीय व्यवसायों के बीच किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि उनमें से लगभग ६५% के पास औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच थी , जो दर्शाता है कि व्यवसाय समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है या कम बैंकिंग सेवाओं से जुड़ा है। क्षेत्रीय असमानताएँ भी देखी गईं, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों (५०%) की तुलना में पहुँच दर (८०%) अधिक थी। केवल ३०% व्यवसायों के पास बीमा कवरेज था, जो स्थानीय व्यवसायों के बीच जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में अंतर को उजागर करता है।

व्यवसायों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में खराब बुनियादी ढाँचा , कम वित्तीय साक्षरता और सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक कारक शामिल हैं। खराब बुनियादी ढाँचा , जैसे कि उचित सड़कों और परिवहन सुविधाओं की कमी , बैंकिंग संस्थानों तक पहुँचने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है , खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी बाधाओं के रूप में उभरती है, खासकर महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए।

लिंग असमानताओं की भी पहचान की गई , जिसमें केवल ४०% महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच की रिपोर्ट की , जबकि पुरुषों के स्वामित्व वाले ७०% व्यवसायों ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच की रिपोर्ट की। युवा व्यवसाय मालिकों (१८-३५ वर्ष की आयु) ने पुराने व्यवसाय मालिकों की तुलना में उच्च वित्तीय साक्षरता स्तर और पहुँच दर प्रदर्शित की। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों द्वारा वित्तीय सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की संभावना अधिक थी।

अध्ययन में वित्तीय सेवाओं तक पहुँच और व्यावसायिक प्रदर्शन के बीच सकारात्मक सहसंबंध पाया गया , पिछले वर्ष की तुलना में ऋण तक पहुँच वाले व्यवसायों ने २५% की औसत राजस्व वृद्धि दर्ज की , जबकि बिना पहुँच वाले व्यवसायों के लिए यह केवल १०% थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रूप से शामिल व्यवसायों ने रोज़गार सृजन की उच्च प्रवृत्ति प्रदर्शित की , जिसमें प्रति व्यवसाय औसतन ३.५ नए पद सृजित हुए, जबकि वित्तीय पहुँच के बिना व्यवसायों के लिए यह १.२ था।

वित्तीय समावेशन पहलों से लाभान्वित होने वाले व्यवसायों के केस स्टडी में एक स्थानीय कृषि-आधारित व्यवसाय को माइक्रोफाइनेंस ऋण प्राप्त करना शामिल है , जिसके कारण फसल की उपज में ५०% की वृद्धि हुई और मालिक को परिचालन का विस्तार करने की अनुमति मिली।

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि सरगुजा जिले में वित्तीय समावेशन धीरे-धीरे बेहतर हो रहा है , लेकिन महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं जो औपचारिक वित्तीय प्रणाली में पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती हैं। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच और बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन के बीच संबंध वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और अवसंरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है। इन बाधाओं को दूर करके , सरगुजा जिले में उन्नत वाणिज्य और आर्थिक विकास की क्षमता को साकार किया जा सकता है, जिससे आजीविका में सुधार और सतत विकास हो सकेगा।

चर्चा:

वित्तीय समावेशन वाणिज्य और उद्यमिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है , क्योंकि यह छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को अपने संचालन में निवेश करने , संसाधन प्राप्त करने और नकदी प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। सरगुजा जिले में , ऋण तक पहुँच वाले व्यवसायों ने २५% की औसत राजस्व वृद्धि का अनुभव किया , जो इस बात को पुष्ट करता है कि वित्तीय सेवाएँ व्यवसाय विस्तार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। बीमा उत्पादों की कम उपयोग दर (३०%) स्थानीय व्यवसायों के बीच जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करती है , जो यह सुझाव देती है कि उपलब्ध बीमा उत्पादों के बारे में व्यवसाय मालिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता पहल उनके लचीलेपन को और बढ़ा सकती है।

विश्लेषण वित्तीय समावेशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव को प्रकट करता है , क्योंकि वित्तीय सेवाओं तक पहुँच वाले व्यवसाय न केवल विकास का अनुभव करते हैं , बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक गतिविधि में वृद्धि में भी योगदान करते हैं। यह सरमा (२०१०) के काम से मेल खाता है , जिन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाता है , जिससे व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

अध्ययन सरगुजा जिले में वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए कई सिफारिशें सुझाता है। इनमें समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना , परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश के माध्यम से बुनियादी ढांचे में सुधार करना , वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना और जिले में व्यवसायों के

सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग करना शामिल है। इन सिफारिशों का उद्देश्य निवासियों को सूचित निर्णय लेने और उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है , विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं जैसे विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों को लक्षित करना। इन कार्यक्रमों का नियमित मूल्यांकन अंतराल की पहचान करने , उनकी प्रभावशीलता को मापने और जिले में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भविष्य के नीतिगत निर्णयों को सूचित करने में मदद कर सकता है।

इस अध्ययन के निष्कर्ष सरगुजा जिले में वाणिज्य और आर्थिक विकास को बढ़ाने में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। व्यवसायों को सशक्त बनाने , रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के माध्यम से, वित्तीय समावेशन सतत विकास के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करता है। हालांकि , वित्तीय साक्षरता तक पहुँचने और सुधारने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार और वित्तीय संस्थानों दोनों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। वित्तीय समावेशन की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना आवश्यक होगा , यह सुनिश्चित करते हुए कि समुदाय के सभी सदस्य आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकें और उनसे लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष:

जनजातीय वाणिज्य सरगुजा जिले की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है , जो जनजातीय समुदायों की आजीविका और व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यह पारंपरिक हस्तशिल्प , कृषि उत्पादों और वन-आधारित वस्तुओं के माध्यम से आय उत्पन्न करता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है। मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में जनजातीय वाणिज्य का एकीकरण अधिक आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देता है , एक ही क्षेत्र पर निर्भरता को कम करता है और आर्थिक झटकों के खिलाफ लचीलापन प्रदान करता है। यह पारंपरिक शिल्प और प्रथाओं को प्रदर्शित करके सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देता है , जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता है। हालांकि , वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच , अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और बाजार बाधाओं जैसी चुनौतियां इसकी क्षमता में बाधा डालती हैं। सरगुजा जिले में जनजातीय वाणिज्य की क्षमता को अधिकतम करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार , आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और बाजार संपर्क बढ़ाने जैसी पहल आदिवासी उद्यमियों को सशक्त बनाएगी और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करेगी।

संदर्भ:

1. *Archana, H. N. (2013). Financial inclusion–role of institutions. Innovative Journal of Business and Management, 2(4), 44-48.*
2. *Bhattacharya, R., & Ranjan, P. (2016). The interplay between financial inclusion and rural development in India. Journal of Rural Economics, 8(2), 45-58.*
3. *Bansal, M. K. (2017). Role of Reserve Bank of India in Indian economy. International Journal of Business Administration and Management, 7(1), 45-59.*
4. *Dharmendra, M., Trivedi, H., & Mehta, N. K. (2016). Indian kisan credit card scheme: An analytical study. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, 6(1), 23-27.*
5. *Dixit, R., & Ghosh, M. (2013). Financial inclusion for inclusive growth of India-A study of Indian states. International Journal of Business Management & Research, 3(1), 147-156.*
6. *Financial inclusion in India-Assessment. (2013). Speech delivered by Shri P. Vijaya Bhaskar, Executive Director, Reserve Bank of India at the MFIN and Access-Assist Summit organized in New Delhi.*
7. *Garg, A., & Agarwal, P. (2014). Financial inclusion in India: A review of initiatives and achievements. Journal of Business and Management, 16(6), 52-61.*
8. *Ghosh, S., & Sahu, A. (2014). Challenges of financial inclusion in rural India. Journal of Economic Policy and Development, 12(3), 67-83.*
9. *Government of India, Ministry of Finance-Department of Financial Services. (2011). Strategy and guidelines on financial inclusion.*
10. *Indian Institute of Banking and Finance. (2008). Principles Practices of Banking (2nd ed.). Gurgaon: Macmillan.*
11. *Ibrahim, M. S. (2011). Operational performance of Indian scheduled commercial banks-an analysis. International Journal of Business and Management, 6(5), 120.*

12. *Iqbal, B. A., & Sami, S. (2017). Role of banks in financial inclusion in India. Contaduría y Administración, 62(2), 644-656.*
13. *Jaiswal, V. (2014). Commercial development of mining areas in central India: Opportunities and challenges. Journal of Economic Development and Planning, 6(3), 89-102.*
14. *Kropp, E. W., & Suran, B. S. (2002, November). Linking banks and (financial) self-help groups in India: An assessment. In Seminar on SHG-bank Linkage Programme, New Delhi, NABARD.*
15. *Kumar, S., & Gupta, A. (2015). The role of financial inclusion in promoting economic development in India. Journal of Economic Studies, 9(1), 33-50.*
16. *Nayak, S. (2015). Impact of government policies on commercial development in backward regions. International Journal of Policy Sciences and Development, 8(4), 55-67.*
17. *Pathak, B. V. (2010). The Indian financial system: Markets, institutions and services. India: Pearson Education.*
18. *PMJDY. Available at: https://pmjdy.gov.in/*
19. *Raman, A. (2012). Financial inclusion and growth of the Indian banking system. IOSR Journal of Business and Management, 1(3), 25-29.*
20. *Rangarajan, C. (2008). Report of the Committee on Financial Inclusion. Ministry of Finance, Government of India.*
21. *Rao, S. (2002). Barriers to e-commerce adoption in rural economies: Connectivity, literacy, and language issues. Journal of Rural Technology & Innovation, 4(1), 35-44.*
22. *Reserve Bank of India. (2011). Report on the status of financial inclusion in India. Reserve Bank of India.*
23. *Saxena, A. (2016). Policy landscape for e-commerce and digital payments in rural India: Bridging the divide. Journal of Policy Research, 15(2), 85-102.*
24. *Sharma, P., & Tuli, R. (2012). Financial inclusion plans (FIPs)–Growing roots in the light of "Good Governance" of RBI. International Journal of Management, IT and Engineering, 2(8), 597-604.*
25. *Shabna (2014). Financial inclusion: Concepts and overview in Indian context. Abhinav International Monthly Referred Journal of Research in Management & Technology, 3(6), 28-33.*
26. *Singh, B. K. (2011). A study on investors' attitude towards mutual funds as an investment option. Journal of Asian Business Strategy, 1(2), 8.*
27. *Singh, P., & Kumar, R. (2015). Effects of financial inclusion on economic empowerment across Indian states. International Journal of Social and Economic Research, 14(3), 101-117.*
28. *Singh, S. (2019). Benefits of financial inclusion to India. Available at: https://indiamicrofinance.com/benefits-financial-inclusion-india/*
29. *Stand up India. Available at: https://standupmitra.in/Home/AboutUs*
30. *Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. Review of Development Finance, 6(1), 46-57.*